(घ) और (ङ) जी हां। वित्त घोषणा की अनुमोदित प्रणाली के अनुसार, 1740 करोड़ रु० की राशि महापत्तनों, अंतर-निगम ऋणों और प्रयोक्ताओं के आंतरिक संसाधनों में से जुटाई जाएगी। शेष 1244 करोड़ रु० की राशि बजटीय सहायता के माध्यम से उपलब्ध होने की आशा है जिसमें लगभग 946 करोड़ रु० का विदेशी मुद्रा अंश भी शामिल है।

Improvement of Roads

6317. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government are considering to give a new shape to roads and devclop a new road policy; and

(b) if so, the details thereof and the reasons for devising such a policy?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) and (b) In view of constraint of budgetary resources, the Government is contemplating to invite private sector participation for development of National Highways. Under the scheme, the private entrepreneurs will be asked to develop a highway facility from their own resources and will be granted permission to collect fees from the user for a specified period whereafter the facility will revert to the Government.

Demurrage to Ship Owners

6318. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) how much foreign exchange has been paid in the financial years 1992-93, 1993-94 and 1994-95 as demurrage (waiting cost) to ship owners, Indian or foreign, for ships waiting to discharge/pick up dry cargo for import and export at ports in India; and

(b) how much of this demurrage was paid specifically for the import of fertilizers in the same financial years?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) and (b) The ports do not pay demurrage or waiting cost to ship owners for ships waiting to discharge/pick up dry cargo at ports; nor do the ports charge demurrage on such ships. The charges towards ships' waiting cost, if any, are being paid by the importers/exporters to the ships owners or their agents directly without inolving the ports in any manner. Such charges, as a normal practice, are included either in the freight and incidental charges or in the terms and conditions of the charter party agreements between the shippers and the shipping lines concerned.

The majority of the importers/exporters, particularly after liberalisation and decontrol of many commodities by the Government, are private parties. Therefore, no statistics are being maintained about the monies paid by one private party to another; nor would it be practicable in view of the fact that thousands of importers/exporters are dealing in multitudes of products/commodities, through shipping lines the world over, at various minor and major ports in India.

Development of Rewa Board in Muzaffarpur

6319. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) the participation of the Ministry of Surface Transport in the development of the REWA board of Muzaffarpur District of Bihar, which has been taken over by Japan for improvement as Budhist Centre at Vaishali?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): The Central Government is primarily responsible for development and maintenance of National Highways in the country and all roads other than National Highways is essentially the responsibility of the concerned State. Presumably the

Hon'ble Member is seeking information about development of Rewa Ghat road of Muzaffarpur District in Bihar. Ministry of Surface Transport has no participation in the said project.

इलाहाबाद-पटना खंड में नौचालन संबंधी सुविधाएं

6320. श्री ईश दत्त यादव:
श्री आस मोहम्मद:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार यातायात की मांग को देखते हुए इलाहाबाद-पटना खंड में नौचालन संबंधी सुविधाओं का विकास करने वाली है;

(ख) इस संबंध में किये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त खंड में नौचालन संबंधी सुविधाएं कब तक उपलब्ध हो जायेंगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) जी हां।

(ख) और (ग) इलाहाबाद-पटना खंड, राष्ट्रीय जलमार्ग-1 का एक भाग है जो हल्दिया से इलाहाबाद तक जाता है और अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए इलाहाबाद-पटना खंड का चरणों में विकास किया जायगा। तथापि, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की कार्य योजना के अनुसार विकास हेतु यही है कि इस संबंधी अध्ययन के सर्वेक्षण की निगरानी के लिबाय आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस खंड में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास का वित्तपोषण कोई प्रस्ताव नहीं है। उसके बाद आई डब्ल्यू ए आई का अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना में इलाहाबाद—पटना खंड में विकास कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है जो योजना प्रावधान और उस क्षेत्र में भाड़ों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

महानगरों में सड़क दुर्घटनाएं

6321. श्री आस मोहम्मद:
श्री ईश दत्त यादव:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले छः महीनों के दौरान महानगरों में कुल कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) उक्त दुर्घटनाओं के कारण कितनी वित्तीय हानि हुई तथा कितने व्यक्ति मारे गये;

(ग) इस संबंध में कितने लोगों को दंडित किया गया; और

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय सड़क निधि में वृद्धि

6322. श्री महेश्वर सिंह: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संकल्पों के अनुसरण में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत के आधार पर तथा उससे प्राप्त होने वाले कर को ध्यान रखते हुए राज्यों में केन्द्रीय सड़क निधि में वृद्धि कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार कब तक अंतिम निर्णय ले लेगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) से (ग) इस बारे में संसद ने 1988 में एक संकल्प पारित किया था लेकिन उसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। मामला सरकार के पास विचाराधीन है और अभी से यह बता पाना संभव नहीं है कि इस बारे में कब अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

गंगा और कावेरी नदियों में माल की ढुलाई तथा यात्री-परिवहन

6323. श्री शंकर दयाल सिंह: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंगा और कावेरी नदियों में माल की ढुलाई तथा यात्री-परिवहन सेवाएं प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) और (ख) गंगा नदी, राष्ट्रीय जलमार्ग-1 में माल और यात्रियों का परिवहन काफी समय पहले से ही किया जा रहा है। गंगा नदी में